आउटकम बजट 2018–19

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0– SDG-1, SDG-5, SDG-9, SDG-11, SDG-16 & SDG-17

विभाग का नाम– सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आई0टी0डी0ए0)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउटले / बजट		SDG Goals/ Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटपुट) वर्ष 2018–19	01.04.2017 की स्थिति (बेस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटकम)	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1.	क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) का क्रियान्वयन	योजना में स्वतंत्र सरकारी नेटवर्क स्थापित कर इसके माध्यम से G2C एवं G2G सेवायें उपलब्ध कराई जायेगी।	1500.00	1500.00	SDG 9	• बैंडविड्थ अपग्रेडेशन तहसील / ब्लॉक– 10Mbps - 11 sites	बैंडविड्थ ब्लॉक / तहसील स्तर 2 Mbps	स्वान के अन्तर्गत कनेक्टेड राजकीय विभागों / कार्यालयों / इकाईयों के ई–शासन कार्य प्रणाली तथा कार्य सम्पादन में वृद्धि।	एक वर्ष
						• बैंडविड्थ अपग्रेडेशन तहसील / ब्लॉक पोप– 34Mbps -- 28 sites	वर्टीकल बैंडविड्थ राज्य मुख्यालय से जनपद मुख्यालय स्तर 10 Mbps		
						• बैंडविड्थ अपग्रेडेशन जनपद 50Mbps - 13 DHQ	तकनीकी मानव संसाधन तैनात– 197		
						• तकनीकी मानव संसाधन तैनात– 230	प्वाइंट ऑफ प्रिर्जेन्स (पोप) केन्द्र– 133		
						• प्वाइंट ऑफ प्रिर्जेन्स केन्द्र संचालन– 135	हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी – 1098		
						• हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी स्थापित–1000	हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी में होस्ट– 3647		
						• रेडियो फ्रिक्वेंसी सेटअप – 135 पोप	NKN से एकीकरण जनपद मुख्यालय– 10		
						• नेटवर्क का पूर्ण अपग्रेडेशन	स्वान से आच्छादित मुख्य विभाग – 30		
2.	राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण	राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा सूचना प्रौद्योगिकी पहल से राज्य में आई0टी0 का सुदृढ़ीकरण	400.00		SDG 9 SDG 8 SDG 5	• आई0टी0 भवन तथा आई0टी0डी0ए0 कार्यालय का संचालन एवं अनुरक्षण।	• सू0प्रौ0 के प्रशासनिक नियंत्रण में एजेंसी–आई.टी.डी.ए. का संचालन	सूचना प्रौद्योगिकी भवन में आई0टी0 की गतिविधियों–स्टेट डाटा सेंटर, स्वान संचालन केन्द्र से ई–गवर्नेन्स / गुड गवर्नेन्स तथा नागरिकों को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से सेवायें प्रदान करना।	एक वर्ष
						• मानव संसाधन तैनात– 23	• मानव संसाधन तैनात– 20		
						• भवन अनुरक्षण – 1	• भवन अनुरक्षण – 1		
		मा0 मुख्यमंत्री डैश बोर्ड के अन्तर्गत सभी विभागों को सम्मिलित किया जायेगा। एन.टी.आर.ओ. भारत सरकार से आरम्भ में पांच वर्ष तथा एन.सी.आई.आई.पी.सी. के साथ एक वर्ष के एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है, जिनके माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी भवन में ड्रोन तकनीकी पर शोध तथा प्रशिक्षण हेतु लैब एवं साईबर सिक्योरिटी पर प्रशिक्षण हेतु केन्द्र की स्थापना कर IT क्षेत्र के छात्रों / प्रोफेशनल को 6 माह का प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त रोजगार का अवसर प्राप्त होगा।				• डैश बोर्ड / एप्लीकेशन्स संचालन 1		मुख्यमंत्री डैश बोर्ड की स्थापना कर विभागों तथा परियोजनाओं की अनुश्रवण कर विभागीय कार्यक्षमता में वृद्धि, पारदर्शिता, एकाउण्टेबिलिटी में सुधार।	
						• डैश बोर्ड पर विभागों के के.पी.आर. जोड़ना 15			
						• नेशनल इनफारमेशन सेंटर के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित नेटवर्क उपकरणों का अनुरक्षण– 1 जनपद		जनपद हरिद्वार में एन.आई.आई. के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर तक हॉरिजोन्टल कनेक्टिविटी प्रदान करना।	
						–NTRO, भारत सरकार के माध्यम से ड्रोन एप्लीकेशन एवं शोध लैब का संचालन– 1 – एन.सी.आई.आई.पी.सी. के माध्यम से साईबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन – 1 25–25 के बैच में छः माह का प्रशिक्षण		राज्य में द्रोण तकनीकी पर शोधकर्ताओं तथा प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित कर रोजगार का अवसर– 50 साईबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर रोजगार का अवसर प्रदान करना – 50	
3.	नेशनल ई–गवर्नेन्स योजना	केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न अवयवों यथा– स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना, कॉमन सर्विस सेन्टरों की स्थापना, ई–डिस्ट्रिक्ट का क्रियान्वयन एवं राज्य में क्षमता विकास क्रियान्वयन		500.00	SDG 8 SDG 9 SDG 5	• स्टेट डाटा सेंटर – 01 SDC	–	राज्य के नागरिकों को विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली राजकीय सेवाओं को नागरिकों के निकट इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराते हुए डिजिटल इण्डिया की परिकल्पना को पूर्ण करना। नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में पारदर्शिता / गति तथा गुणवतता सुनिश्चित कर ई–गवर्नेन्स एवं गुड गवर्नेन्स की स्थापना। CSC संचालन से ग्रामीण उद्यमियों को स्वरोजगार का साधन उपलब्ध कराना।	एक वर्ष
						• कॉमन सर्विस सेंटर संचालन 9750 CSC	स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर – 6103 CSC		
						• सी.एस.सी. के माध्यम से नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विस्तार B2C & G2C	ई–डिस्ट्रिक्ट सेवाओं हेतु अधिकृत सेंटर – 2622 CSC		
						• ई–डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत राज्यकीय सेवाओं का डिजिटाईजेशन 29 सेवायें	E-Dist के अन्तर्गत उपलब्ध सेवायें पौड़ी– 15		
						• Common Application Portal (CAP) विकसित करना।	E-Dist के अन्तर्गत सेवायें अन्य जनपद– 8		
						• CAP पर राज्य के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित चिन्हित सेवाओं को आरम्भ करना।	E-DIst में निस्तारित आवेदन–33.80 लाख		
							ई–डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के कुशल संचालन हेतु स्थापित हैल्प डेस्क – 4		
							तहसील स्तर तक स्थापित E-Dist केन्द्रों– 131		

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउटले/बजट		SDG Goals/ Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटपुट) वर्ष 2018–19	01.04.2017 की स्थिति (बेस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटकम)	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
4	राज्य के प्रमुख सरकारी कार्यालयों / सार्वजनिक स्थलों पर वाई–फाई जोन स्थापित किया जाना	राज्य के प्रमुख सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक स्थलों पर वाई–फाई जोन स्थापित किया जाना		200.00	SDG 8 SDG 9 SDG 5	• राज्य के प्रमुख सरकारी कार्यालयों में वाई –फाई जोन की स्थापना की जायेगी, तथा साथ ही आवश्यक सार्वजनिक स्थलों पर वाई–फाई जोन स्थापित किये जायेंगे।	मसूरी तथा नैनीताल में वाई–फाई जोन की स्थापना।	राजकीय कार्यालयों में डिजिटल वातावरण से कार्यक्षमता को विकसित किया जायेगा।	एक वर्ष
4	ब्लॉक / तहसील स्तर तक वीडियो कान्फ्रेंसिंग	जनपद मुख्यालय, ब्लॉक एवं तहसील मुख्यालय तक वीडियो कान्फ्रेंसिंग सिस्टम की स्थापना।		236.00	SDG 9	• वीडियो कान्फ्रेंसिंग सिस्टम से आच्छादित स्थल (समस्त जनपद मुख्यालय, सचिवालय, तहसील तथा ब्लॉक मुख्यालय एवं हरिद्वार जनपद में ग्राम पंचायत स्तर तक)– 621	• राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा जिला प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (डायट्स) एवं – 11 स्थल	ब्लॉक एवं तहसील स्तर तक परियोजनाओं/ कार्यो की समीक्षा एवं अनुश्रवण से राजकीय कार्यों में गति प्राप्त होगी, राजकीय सूचना तंत्र का सुदृढ़ीकरण होगा तथा ई–गवर्नेन्स एवं गुड गवर्नेन्स का विकास।	एक वर्ष
	योग		**1900.00**	**2436.00**					

राज्य बजट के अतिरिक्त केन्द्र स्कीम इत्यादि के अन्तर्गत कार्य

1	नेशनल इन्फॉरमेशन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर (एन.आई.आई.)	परियोजना के पॉयलट कियान्वयन हेतु देश के 8 जनपदों में जनपद हरिद्वार का चयन किया गया है, जहां पर 220 ग्रामपंचायत में कनेक्टिविटी प्रदान कर प्रत्येक ग्रामपंचायत में न्यूनतम तीन कार्यालयों (विद्यालय, चिकित्सा केन्द्र, आंगनवाणी इत्यादि) को कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है।			SDG 9	• हरिद्वार जनपद मुख्यालय से 6 तहसील/ब्लॉक तक 50Mbps– 6 तहसील/ब्लॉक मुख्यालय • तहसील/ब्लॉक से ग्राम पंचायत स्तर तक 10Mbps – 220 ग्राम पंचायत • ग्राम पंचायत स्तर से हॉरिजॉन्टल ऑफिस 10Mbps – 374 स्थल	–	जनपद हरिद्वार में ग्राम पंचायत स्तर तक तथा उसके अन्तर्गत हॉरिजान्टल कार्यालय (सरकारी संस्थाओं) को स्वान नेटवर्क से संयोजित किया जायेगा, जिससे ग्राम पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी का उपयोग कर राजकीय कार्यों का कुशल सम्पादन हो सकेगा।	एक वर्ष
2	प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान	सी0एस0सी0 एस.पी.वी. इण्डिया लिमिटेड के साथ आई0टी0डी0ए0 द्वारा एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है, जिनके द्वारा राज्य के समस्त कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ग्रामीणों को डिजिटल साक्षरता प्रदान किया जायेगा।			SDG 1 SDG 5	• ग्रामण स्तर पर स्थापित CSC – 5900 • डिजिटल साक्षरता प्रदान – 4.51 लाख • अन्य प्रशिक्षण पार्टनर – 14		राज्य के ग्रामण क्षेत्रों में नागरिकों को कॉमन सर्विस सेंटर तथा अन्य प्रशिक्षण पार्टनर के माध्यम से ग्रामीणों को डिजिटल साक्षरता प्राप्त होगी। – 600900 ग्रामीण प्रशिक्षण हेतु CSC संचालक–ग्रामीण उद्यमी को भारत सरकार द्वारा भुगतान किया जायेगा, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय का साधन प्राप्त होगा। – 5900 ग्रामीण उद्यमियों को आय का स्रोत प्राप्त होगा, जिसमें वर्ष में लगभग 1353 लाख की आय प्राप्त होगी।	एक वर्ष
3	एरोस्टेट (बैलून) प्रोजेक्ट	एन.ई.जी.डी. भारत सरकार द्वारा राज्य में एरोस्टेट पायलेट प्रोजेक्ट हेतु वित्त पोषण किया गया है। परियोजना के अन्तर्गत माध्यम से राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में एरोस्टेट (बैलून) के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान की जायेगी।			SDG 9 SDG 17	• आई.आई.टी. मुंबई के माध्यम से पायलट परियोजना के रूप में राज्य के शैडो क्षेत्र / डार्क स्पोर्ट में वैलून की स्थापना।	–	राज्य के दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुविधा का सुदृढ़ीकरण एवं इण्टरनेट सुविधा उपलब्ध कराना। विद्युत आपूर्ति में असुविधा/ प्राकृतिक आपदा/ आपातकालीन परिस्थितियों में भी संचारण की संभावना स्थापित हो पायेगी।	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउटले / बजट		SDG Goals/ Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटपुट) वर्ष 2018–19	01.04.2017 की स्थिति (बेस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटकम)	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
4	आधार	सभी नागरिकों के आधार पंजीकरण कर विभिन्न विभागों के माध्यम से नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को आधार प्रयोजित कर नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करना।			SDG 16	• आधार पंजीकरण– 100%	• 107 लाख की जनसंख्या के सापेक्ष कुल आधार पंजीकृत–104 लाख	राज्य के नागरिकों का 100 प्रतिशत आधार पंजीकरण कर राज्य के सभी विभागों जिनके माध्यम से नागरिकों को सीधे भुगतान होते हैं, को आधार सीडिंग के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ प्रदान कर ई–गवर्नेन्स / गुड गवर्नेन्स स्थापित कर पारदर्शिता एवं त्वरितता प्राप्त होगी। आधार सीडिंग से लाभार्थियों की डुप्लीकेशी होने की संभवना क्षीर्ण होगी, जिससे सरकारी धन का अपव्यय रूकेगा। वास्तविक लाभार्थी को उसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकेगा।	3 वर्ष
						• ग्राम्य विकास के अन्तर्गत मनरेगा हेतु आधार सीडिंग– 100%	• ग्राम्य विकास के अन्तर्गत मनरेगा हेतु आधार सीडिंग– 99%		
						• खाद्य एवं आपूर्ति के अन्तर्गत पी.डी.एस. एवं एल.पी.जी. हेतु आधार सीडिंग– 100%	• खाद्य एवं आपूर्ति के अन्तर्गत पी.डी.एस. एवं एल.पी.जी. हेतु आधार सीडिंग– 84%		
						• डी0बी0एल0टी0 हेतु आधार सीडिंग– 100%	• समाजकल्याण में वृद्धा एवं विधवा पेंशन हेतु– 100%		
						• समाजकल्याण के विकलांग पेंशन हेतु– 100%	• समाजकल्याण में विकलांग पेंशन हेतु–		
						• बैंकिंग के अन्तर्गत जनधन तथा ई.पी.एफ. हेतु– 100%	• प्रधानमंत्री जनधन तथा EPF हेतु– 17%		
							• मनरेगा के अन्तर्गत आधार प्रदत सेवायें– 42%		
							• एल.पी.जी. के अन्तर्गत आधार प्रदत सेवायें– 59%		
							• एन.एस.ए.प. के अन्तर्गत आधार प्रदत सेवायें– 10%		